मनमानी

नारायणगंज बस स्टैंड चौपाटी पर अव्यवस्था हावी, बिना सील-साइन की पर्ची थमाकर हर महीने वसूले जा रहे 1000 रुपये

पैसे वसूलने के बाद भी सुविधाएं शून्य

धंधा चौपट, ऊपर से अधिकारियों की धमकी

दुकानदारों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि चौपाटी को अंदर की तरफ शिफ्ट कर देने के कारण ग्राहकों का आना कम हो गया है, जिससे उनका धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। ऐसे में हर महीने का एक हजार रूपए का किराया देना भारी पड़ रहा है। जब दुकानदार असमर्थता जताते हैं, तो पंचायत कर्मी आकर उन्हें धमकाते हैं कि यदि समय पर राशि नहीं दी तो उनके ठेलों को चौपाटी से बाहर फेंक दिया जाएगा। पीड़ित दुकानदारों ने जिला प्रशासन और संबंधित उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।

नारायणगंज, नवभारत। जनपद पंचायत नारायणगंज के अंतर्गत पड़रिया उर्फ नारायणगंज बस स्टैंड पर बनाई गई चौपाटी इन दिनों पंचायत की मनमानी और अव्यवस्था का केंद्र बन चुकी है। पड़रिया ग्राम पंचायत द्वारा राज्य परिवहन की भूमि पर कब्जा जमाकर यहाँ चाय, नाश्ता और पान के ठेले वालों के लिए एक चौपाटी नुमा जगह बनाई गई थी। दावा था कि इससे अव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन आज यहाँ के छोटे दुकानदार खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पंचायत द्वारा हर महीने मोटी रकम वसूलने के बावजूद दुकानदारों को बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो रही हैं।

दुकानदारों का आरोप है कि पंचायत द्वारा उनसे अमानत के तौर पर दो हजार और हर महीने किराये के रूप में एक हजार की वसूली की जा रही है। इसके अलावा साफ-सफाई के नाम पर 50 प्रति सप्ताह अलग से लिए जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वसूली के बदले जो रसीद दुकानदारों को दी जाती है, उसमें न तो पंचायत की आधिकारिक सील है और न ही सरपंच के हस्ताक्षर। रसीद पर केवल सचिव के हस्ताक्षर की एक चिड़िया बनी होती है, जिससे इस पूरी वसूली के सरकारी खाते में जाने पर संदेह खड़ा हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि भीषण गर्मी और अब आने वाली बरसात में पाल तिरपाल लगाने तक की जगह नहीं दी गई है। पंचायत गाँव के अन्य रसूखदारों और दुकानदारों को तो सुविधाएं दे रही है, लेकिन हर महीने ईमानदारी से पैसा देने वाले गरीब ठेले वालों को खुले आसमान के नीचे व्यापार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

185 शिक्षकों को मिला पांच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण

आकांक्षी विकासखण्ड योजना के तहत समावेशित शिक्षा प्रशिक्षण का समापन

नारायणगंज, नवभारत। आकांक्षी विकासखण्ड योजना अंतर्गत विकास खण्ड नारायणगंज में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार समावेशित शिक्षा के तहत शिक्षकों का पांच दिवसीय मल्टी-कैटेगरी प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 से 13 जून तक शासकीय मॉडल स्कूल कुड़ामैली में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्रद्धा सोनी के नेतृत्व में सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।

विकास खण्ड एमआरसी शेख इरफान ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में सीडब्ल्यूएसएन (दिव्यांग) बच्चों को शिक्षित करने वाले 173 शिक्षकों तथा 12 जन शिक्षकों सहित कुल 185 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षकों को समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा तथा विशेष शिक्षण तकनीकों की जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को बताया गया कि दिव्यांग बच्चों का विद्यालयों में सामान्य बच्चों की तरह नामांकन सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को समझते हुए उनके साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार किया जाए। साथ ही, बच्चों को सहज एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उनकी शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम में ब्रेल लिपि के उपयोग, सांकेतिक भाषा के व्यावहारिक प्रशिक्षण, बच्चों के अधिगम स्तर के मूल्यांकन, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान और उनके अनुरूप शिक्षण पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने शिक्षकों को दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्यधारा से जोड़ने, उनमें आत्मविश्वास विकसित करने तथा हर प्रकार की प्रतियोगिता और गतिविधि में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। जिला परियोजना समन्वयक कुलदीप कटहल द्वारा समावेशित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस अवसर पर जिले के समावेशित शिक्षा प्रभारी सहायक परियोजना समन्वयक के.के. उपाध्याय ने कहा कि समावेशित शिक्षा केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्रदान करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों में अपार प्रतिभा होती है, आवश्यकता केवल उन्हें उचित मार्गदर्शन, सहयोग और अनुकूल वातावरण प्रदान करने की है।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी कमलेश भवेदी ने कहा कि समावेशित शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों के रूप में संदीप सोनी, प्रशांत वैद्य, अरविंद यादव, सीमा यादव, शेख इरफान, पंकज उईके, शंकरिया उईके एवं शालिनी ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया। समापन समारोह में जिले के समावेशित शिक्षा प्रभारी के.के. उपाध्याय, शासकीय महाविद्यालय कुड़ामैली के प्राचार्य एडमोन लकणा, मॉडल स्कूल कुड़ामैली के प्राचार्य चितामणि वैष्णव, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजेश विश्वकर्मा, बीआरसी कमलेश भवेदी, बीएसी चरनलाल झारिया, राजीव वर्मा, नवनीता दुबे सहित अन्य अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। विकासखण्ड एमआरसी शेख इरफान ने कहा कि समावेशित शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

सोफे के अंदर छिपाकर रखी शराब जब्त

आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज

मंडला। जिले में अवैध शराब के निर्माण और विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी एवं (प्र.) सहायक जिला आबकारी अधिकारी शैली सैयाम के मार्गदर्शन में मंडला वृत्त में दबिश दी गई।

कार्रवाई के दौरान आबकारी टीम ने महाराजपुर क्षेत्र के कारिकोंन में आरोपी राज चक्रवर्ती के घर पर औचक तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर के सोफे के अंदर शातिर तरीके से छुपाकर रखी गई देसी और विदेशी मदिरा बरामद हुई। टीम ने मौके से 10 नग एमडी व्हिस्की, 12 नग आरएस व्हिस्की, 10 नग एमडी रम और 30 नग देशी मदिरा प्लेन जब्त की। इसके साथ ही टीम ने ग्राम पेटेगांव में भी एक अन्य घर की तलाशी ली, जहां से 10 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची मदिरा बरामद की गई।

अवैध रूप से मदिरा का विक्रय करने वाले आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक सर्वेश नागवंशी सहित आरक्षक भानु पुसम, सत्यपाल मरावी, शकुंतला सैयाम और नेतराम ककोटिया मुख्य रूप से शामिल रहे।

मेरे मरणोपरांत किसी के काम आ सकें मेरी आंखें : संजय तिवारी

नारायणगंज स्वास्थ्य केंद्र में फॉर्म भरकर ली जीते-जी नेत्रदान की प्रतिज्ञा

मंडला। नेत्रदान-महादान के संकल्प को चरितार्थ करते हुए नारायणगंज क्षेत्र में मानवता की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। विकासखंड नारायणगंज के ग्राम करहैया नगरार निवासी संजय तिवारी ने समाज कल्याण और सेवा भावना की दिशा में एक अनुकरणीय कदम उठाया है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगंज पहुंचकर अपनी स्वेच्छा से नेत्रदान करने की घोषणा की है।

जानकारी अनुसार संजय कुमार तिवारी पिछले कुछ समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगंज में पदस्थ नेत्र चिकित्सा सहायक जयकरण चौधरी के संपर्क में थे। श्री चौधरी द्वारा लगातार क्षेत्र में नेत्र सुरक्षा और नेत्रदान को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता प्रयासों से प्रभावित होकर संजय तिवारी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। संजय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वहाँ सीबीएमओ डॉ. अमृतलाल कोल के सम्मुख उपस्थित होकर पूर्ण सहमति के साथ नेत्रदान का आधिकारिक घोषणा पत्र भरा। घोषणा पत्र सौंपने के बाद संजय तिवारी ने अत्यंत भावुक होकर कहा मेरे मरणोपरांत मेरी आंखें समाज के किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के काम आ सकें और उसका जीवन रोशन हो सके, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी या पुण्य नहीं हो सकता।

इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने नेत्रदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया।

एक नेत्रदान, तीन जीवन में ला सकता है उजाला

नेत्र चिकित्सा सहायक जयकरण चौधरी ने बताया कि चिकित्सा विज्ञान के आधुनिक दौर में अब एक व्यक्ति द्वारा किए गए नेत्रदान मतलब दोनों कॉर्निया से लगभग 3 दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन को रोशन किया जा सकता है। कॉर्निया की परतों के आधार पर अलग-अलग मरीजों में इसका सफल प्रत्यारोपण किया जाता है।

स्वास्थ्य केंद्र ने की सराहना, क्षेत्र के लिए बने प्रेरणास्रोत

संजय तिवारी के इस मानवीय कदम की सीबीएमओ डॉ. अमृतलाल कोल और नेत्र चिकित्सा सहायक जयकरण चौधरी सहित पूरे अस्पताल स्टाफ ने सराहना की है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में आज भी अंगदान और नेत्रदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। ऐसे समय में संजय तिवारी जैसे जागरूक नागरिक का आगे आकर स्वेच्छा से घोषणा पत्र भरना पूरे नारायणगंज क्षेत्र के लिए एक मिसाल है।

जिले से कामाख्या सहित मथुरा-वृंदावन की यात्रा जुलाई में

मंडला। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत मंडला जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जुलाई माह में दो विशेष तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय मंडला द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे नागरिक, जो आयकरदाता नहीं हैं, योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। महिलाओं के लिए आयु सीमा में दो वर्ष की छूट का प्रावधान है।

जारी कार्यक्रम के अनुसार पहली यात्रा कामाख्या धाम के लिए 11 जुलाई से 16 जुलाई तक तथा दूसरी यात्रा मथुरा-वृंदावन के लिए 25 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रस्तावित है। दोनों यात्राओं के लिए मंडला जिले को 196-196 यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। कामाख्या यात्रा के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित की गई है, जबकि मथुरा-वृंदावन यात्रा के लिए आवेदन 11 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों की सूची क्रमशः 30 जून एवं 14 जुलाई तक जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा चयनित यात्रियों की जानकारी आईआरसीटीसी को 4 जुलाई एवं 18 जुलाई तक भेजी जाएगी।

इंद्री की दीवारों पर जीवंत हुई जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक गोंडी कला

कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने महिला कलाकारों को किया प्रोत्साहित

मंडला। जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक कला को नई पहचान देने वाली ग्राम पंचायत इंद्री आज अपनी आकर्षक गोंडी पेंटिंग्स के कारण विशेष पहचान बना रही है।

गांव की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर उकेरी गई रंग-बिरंगी गोंडी पेंटिंग्स स्थानीय लोगों के साथ-साथ यहाँ आने वाले आगंतुकों को भी मंत्रमुग्ध कर रही हैं। हाल ही में कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने इंद्री पहुंचकर महिला कलाकारों से मुलाकात की और उनकी अद्भुत कलात्मक प्रतिभा की सराहना की।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिली वैश्विक पहचान-स्वदेशी स्व-सहायता समूह की सदस्य सुमन बंदेवार ने बताया कि गांव की 11 महिला सदस्य बड़ी बारीकी और धैर्य से इस पारंपरिक गोंडी पेंटिंग को तैयार कर रही हैं। अब यह कला केवल गांव की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और गोंड आर्ट मंडला नामक इंस्टाग्राम पेज के जरिए देशभर में इसकी बिक्री हो रही है। इस नवाचार से समूह की प्रत्येक महिला सदस्य को हर महीने औसतन लगभग 7 हजार रुपये की आय हो रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। गांव की सड़कों के किनारे बनाई गई ये पेंटिंग्स जनजातीय जीवन, प्रकृति, पशु-पक्षियों और लोक संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत करती हैं। यह कला न केवल गांव का सौंदर्य बढ़ा रही है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त कर रही है। उल्लेखनीय है कि गोंडी कला को भौगोलिक संकेतक भी प्राप्त हो चुका है, जिससे इसकी विशिष्टता और वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है।

कान्हा नेशनल पार्क में बिक्री केंद्र और प्रशिक्षण की मांग-मुलाकात के दौरान महिला कलाकारों ने कलेक्टर के समक्ष दो महत्वपूर्ण सुझाव रखे। गोंडी पेंटिंग के लिए एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र या वर्कशॉप स्थापित की जाए। कान्हा नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उनकी कलाकृतियों के प्रदर्शन व बिक्री की व्यवस्था की जाए, जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों तक इसकी पहुंच बन सके।

कलेक्टर ने दिया हरसंभव मदद का भरोसा-कलेक्टर श्री धोटे ने महिलाओं के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कहा गोंडी कला हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। इसके संरक्षण, संवर्धन और बेहतर विपणन के लिए प्रशासन हरसंभव कार्य करेगा ताकि कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बाजार मिल सके। मुलाकात के अंत में महिला कलाकारों ने अपनी हस्तनिर्मित गोंडी पेंटिंग और कलात्मक डायरी कलेक्टर को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की।

बिलासपुर-मंडला-जबलपुर रेल लाइन के लिए फिर उठी आवाज

82 साल से फाइलों में दबी योजना, रेलवे बोर्ड पर अपने ही नियमों के उल्लंघन का आरोप

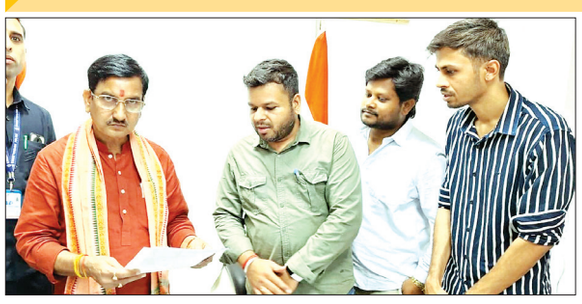

मंडला। मध्य भारत के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बेहद पुरानी और बहुप्रतीक्षित बिलासपुर - मुंगेली-पंडरिया - मंडला - जबलपुर नई रेल लाइन परियोजना को लेकर एक बार फिर मांग तेज हो गई है। स्वतंत्र रेल एक्टिविस्ट नितिन सोलंकी द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत प्रतिवेदन केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू को व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया है, जिसमें उनसे इस मुद्दे को आगामी संसद सत्र में उठाने का आग्रह किया गया है।

सौंपे गए प्रतिवेदन में रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रेलवे बोर्ड के 12 मई 2004 के आदेश के तहत इस परियोजना की हर 10 वर्ष में समीक्षा होना अनिवार्य था। बहरहाल साल 2014 के बाद से आज तक इसका कोई पुनरीक्षण सर्वे नहीं कराया गया है। तय समयावधि बीत जाने के 12 साल बाद भी यह परियोजना केवल फाइलों में ही दबी हुई है। यह रेल परियोजना पहली बार साल 1944 (ब्रिटिश काल) में चर्चा में आई थी। इसके बाद साल 1997 में इसके इंजीनियरिंग-कम-ट्रैफिक सर्वे को मंजूरी मिली, लेकिन 2003-04 में प्रतिफल दर कम होने का हवाला देकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक्टिविस्ट का तर्क है कि अब क्षेत्र में आबादी, औद्योगिक गतिविधियों, पर्यटन और माल परिवहन की संभावनाएं काफी बढ़ चुकी हैं, जिससे इस परियोजना की व्यवहार्यता पहले से कहीं अधिक मजबूत है।

बचेगा समय और पैसा-प्रस्तावित रेल मार्ग जबलपुर और बिलासपुर के बीच वर्तमान में उपलब्ध रेल मार्गों की तुलना में दूरी को लगभग 100 किलोमीटर तक कम कर देगा। इससे न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी, बल्कि मालगाड़ियों के परिचालन खर्च में भी भारी कमी आएगी। इसके साथ ही अमरकंटक, कान्हा, मंडला, मुंगेली और पंडरिया जैसे प्रमुख पर्यटन व सामाजिक केंद्रों को सीधा रेल संपर्क मिल सकेगा।

प्रतिवेदन में इस बात को रेखांकित किया गया है कि छत्तीसगढ़ में कटघोरा - पंडरिया - डोंगरगढ़ रेल परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बिलासपुर - मंडला - जबलपुर रेल लाइन अब सिर्फ एक सामान्य परियोजना नहीं, बल्कि मध्य भारत के रेल नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक बन चुकी है। इसके बनने से महाकौशल, विंध्य और छत्तीसगढ़ के बीच एक सीधा और मजबूत रेल कॉरिडोर तैयार होगा।

जन अभियान परिषद के तत्वावधान में बैठक के पश्चात किया सामूहिक पौधरोपण

मझगांव में पर्यावरण और जल संरक्षण पर मंथन

नारायणगंज। सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद अंतर्गत विकासखण्ड नारायणगंज की प्रगति जनकल्याण समिति के तत्वाधान में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति मझगांव में बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों को प्रकृति और जल स्त्रोतों को बचाने के लिए प्रेरित किया गया। मझगांव में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों ने वर्तमान समय में बदलते मौसम और जल संकट को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के तुरंत बाद सभी उपस्थित सदस्यों और ग्रामीणों ने मिलकर पौधों का रोपण कर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली।

बैठक में अध्यक्ष, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति अरविंद मरावी, सचिव, देवलता उइके, बीजाडांडी से शिवकुमारी उईके, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नन्हीं बाई, इंद्रा उइके और समिति सदस्य फूलवती उइके, अनीता भलावी, बरतो बाई एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर अध्यक्ष ने कहा कि जन अभियान परिषद के माध्यम से गांव-गांव में पर्यावरण चेतना जगाने का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

16 जून से पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती पूर्ण करे शासन

सामाजिक कार्यकर्ता पीडी खैरवार ने उठाई मांग

मंडला। प्रदेश भर के शासकीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के बाद आगामी 16 जून से बच्चों की नियमित कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इसके विपरीत मण्डला जिले में अब तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस लचर व्यवस्था के चलते नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। बच्चों के भविष्य और शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए पालक-अभिभावकों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता एवं पालक महासंघ के जिला अध्यक्ष पी.डी. खैरवार ने मुख्यमंत्री, लोक शिक्षण संचालनालय, जिला कलेक्टर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारी से 16 जून से पूर्व भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की पुरजोर मांग की है।

मई बीतने के बाद भी नहीं आया बुलावा, अतिथि शिक्षकों में रोष-बताया गया कि ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय 8 जून से ही खुल चुके हैं। इससे पहले अप्रैल माह में परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व भी पूरे महीने कक्षाएं लगाई गई थीं, परंतु बिना परिणाम के किस कक्षा का कोर्स पढ़ाया गया, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। हर सत्र की तरह अप्रैल के अंत में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, लेकिन मई बीत जाने के बाद भी जून के इस दूसरे सप्ताह तक उन्हें दोबारा ज्वाइनिंग के लिए कोई बुलावा नहीं आया है। शासन की इस ढीली नीति के कारण अतिथि शिक्षकों में भारी असंतोष और रोष व्याप्त है।

पालक महासंघ के जिला अध्यक्ष पीडी खैरवार ने प्रशासनिक दूरदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा यदि अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई या उसके बाद खिंचती है, तो 16 जून से शुरू होने वाली पढ़ाई का प्रथम पखवाड़ा पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा।

नवाचार

21 देशों के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को सराहा

मिलेट क्वीन लहरी बाई ने जिले के श्री अन्न को दिलाई वैश्विक पहचान

मंडला। अपनी कड़ी मेहनत, नवाचार और पारंपरिक कृषि ज्ञान के बल पर मंडला जिले की प्रगतिशील कृषक लहरी बाई आज देश ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत का नाम रोशन कर रही हैं। मिलेट क्वीन के नाम से विश्व विख्यात लहरी बाई ने श्री अन्न (मोटे अनाजों) के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार में जो उल्लेखनीय योगदान दिया है, उसने उन्हें आज समूचे कृषि जगत और विशेषकर आदिवासी अंचल के किसानों के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत बना दिया है। श्रीमती लहरी बाई ने वर्षों पहले कोदो, कुटकी, रागी और सांवा जैसे अन्य मोटे अनाजों की लुप्त होती पारंपरिक किस्मों को संरक्षित करने का संकल्प लिया था। उनके इस सराहनीय प्रयास के चलते आज क्षेत्र के सैकड़ों किसान कम लागत और उच्च पोषण मूल्य वाले मिलेट उत्पादन की ओर तेजी से आकर्षित हुए हैं। हाल ही में इंदौर में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रिक्स एग्रीकल्चर समिट 2026 में लहरी बाई ने मंडला जिले का प्रतिनिधित्व किया। समिट में उनके द्वारा लगाए गए मंडला मिलेट स्टॉल ने देश-विदेश से आए कृषि वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। इस दौरान समिट में हिस्सा लेने आए लगभग 21 देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की और मंडला में मिलेट संवर्धन के मॉडल को पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय बताया।

श्रीमती लहरी बाई का दृढ़ विश्वास है कि श्री अन्न केवल एक फसल नहीं है, बल्कि यह सीमांत किसानों की समृद्धि और आम जनता के बेहतर स्वास्थ्य का मुख्य आधार है। आज उनके ही कुशल मार्गदर्शन में मंडला जिले के कई महिला स्व-सहायता समूह और ग्रामीण किसान मिलेट आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इन स्थानीय उत्पादों की बाजार में बढ़ती मांग के कारण ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के नए अवसर प्राप्त हुए हैं।